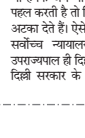

अमृत वाणी

ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहाँ न आदर है, न जीविका, न मित्र, न परिवार और न ही ज्ञान की आशा।

-विनोबा,

संजीवनी और मंथन

मध्यप्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकरदयाल त्रिपाठी को 14 हजार से अधिक मतों से पराजित कर इस क्षेत्र के अपने परम्परागत गढ़ को अपने ही हाथों में बनाए रखने में सफलता हासिल कर ली। सबसे अहम बात यह है कि अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव, देश के अन्य राज्यों एवं लोकसभा के आगामी दिनों में होने वाले चुनावों में स्वयं को पुनर्स्थापित करने के लिए कांग्रेस द्वारा किए जा रहे संघर्ष के परिपेक्ष्य में इस विजय ने जहां एक तरह से संजीवनी के समान कार्य किया है वहीं चौदह वर्षों से राज्य में सत्तारूढ़ दल एवं केन्द्र की भाजपा सरकार को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे कुछ ही माह पूर्व राज्य के भिंड जिले के अटेर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस के हाथों भाजपा को पराजित होना पड़ा था।

विजय खुशी और पराजय चिंता का द्योतक तो होता ही है मगर इससे राज्य या देश के बारे में किसी नतीजे या लहर का अनुमान लगाना भी बहुत जल्दबाजी हो जायगी। फिलहाल इस बात को तो मानना ही होगा कि केन्द्र सरकार की नोटबंदी और लागू किए गए जीएसटी का देशव्यापी प्रतिकूल असर हुआ है और कहना न होगा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। इसी के नतीजे की झलक को इन परिणामों से जोड़कर देखा जा सकता है। साथ ही राज्य की एक के बाद एक खामियां भी इसकी कम जिम्मेदार नहीं है।

विशेष तौर पर इस उपचुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो एक ओर अगर कांग्रेस को आगे के लिए भी अपने संगठित कोशिशों और संघर्ष को जारी रखना होगा वही भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन के बाद अपनी कमजोरियों और चूक को समझकर उन्हें दूर करने का यथासंभव प्रयास करना होगा।

इसमें कोई संशय नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास अपेक्षाकृत अधिक क्षमता और ताकत होती है। चुनाव पूर्व अपने नागरिकों को तरह-तरह से लाभान्वित करके भी वह उनका दिल जीतने और उन्हें स्वयं की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सकती हैं और करती भी है, वहीं विपक्षी दलों के पास अगर कोई ताकत होती है तो वह है उनकी सांगठनिक एकजुटता, इमानदारी और लोगों का भरोसा जीतने की क्षमता जिससे बहुत बड़े उलटफेर भी असंभव नहीं होते।

बड़ी बात यह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को यह बात भलीभांति गांठ बांध लेनी चाहिए कि अब मतदाता वैसे नहीं रहे जिन्हें झुनझुनी पकड़ाकर वश में कर लिया जाय। वे काफी जागरूक हो रहे है। एक दिन में तुष्ट नहीं हो जाते और न ही भरोसा करते है। अगर सत्तारूढ़ दल के पूरे कार्यकाल के प्रदर्शन पर उनकी नजर रहती है तो उस दौरान अन्य दलों की गतिविधियों के प्रति भी वे पूरी तरह सतर्क रहते हैं। चूंकि आम लोगों का वास्ता मुख्यतः जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अधिक रहता है अतः उनका व्यवहार

राजकाज

राहुल के मंदिर जाने पर ऐतराज क्यों

गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साध रखा है लेकिन ऐसे विरोध करने वाले कभी.कभी यह भूल जाते हैं कि उनका विरोध राहुल की लोकप्रियता का कारण बन रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने राहुल के मंदिर जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि श्राम का विरोध करने वाले अब मंदिर.मंदिर जा रहे हैं। इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि राहुल तो मंदिर ही जा रहे हैं लेकिन भाजपा के लोग तो मंदिर के नाम पर सत्ता तक पहुंच जाते हैंए लेकिन फिर यह कहकर सभी को झूठा साबित करते हैं कि उनकी सरकार के एजेंडे में मंदिर निर्माण है ही नहीं। इसलिए यदि राहुल मंदिर जा रहे हैं तो उनका विरोध करने से बेहतर है कि भाजपा अपने चुनावी वादों को याद करे और बताए कि उनमें से कितने वादे पूरे हुए।

चित्रकूट में किसकी हार

चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव भाजपा हार चुकी है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह हार किसकी है क्या इस चुनाव में पार्टी हारी है या फिर प्रदेश के मुखिया की यह हार है दरअसल पार्टी विधायकों और मंत्रियों को अपने क्षेत्र में रहने की नसीहतें देने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अनेक दफा इस बात को कहा था कि जहां उन्हें लगेगा पार्टी कमजोर हो रही है वहां वो खुद जाकर उसे मजबूत करेंगेए लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी उपचुनाव हार गई। यह सरकार में रहते हुए शर्मनाक हार के बराबर है, इसलिए यह कहकर कि 27 सालों में महज एक बार भाजपा इस क्षेत्र से चुनाव जीती है इसलिए यह कांग्रेस का गढ़ है और इस हार का ठीकरा किसी और के सिर पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए सही नहीं है। यहां वाकई कांग्रेस की एकजुटता की जीत है और भाजपा के अंदर आए अहम और दंभ की हार है।

मधुमेह रोग की राजधानी बनता जा रहा है भारत

दुनिया के अधिकतर देशो में 14 नवम्बर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह जिन्हें डायबिटीज भी कहा जाता हैं तेजी से बढ़ रहा एक भयंकर रोग हैं, जो युवा से वृद्ध किसी उम्र के व्यक्ति को हो सकता हैं। निरन्तर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया। इस हेतु उन्होंने 14 नवम्बर का दिन चयनित किया। 14 नवम्बर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस का अलग ध्येय होता है। इसे देखते हुए विश्व मधुमेह दिवस वर्ष-2017 की थीम महिलाएं व मधुमेह स्वास्थ्य हमारा अधिकार रखी है।

आज विश्व मधुमेह दिवस पर विशेष

मधुमेह रोग के कारण एवं इसके विभिन्न पहलुओं को समझने हेतु कई लोग प्रयासरत थे। इनमें से एक जोड़ी फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट की भी थीए जो पैनक्रियाज ग्रन्थि द्वारा स्त्रावित तत्त्व के रसायनिक संरचना की खोज में लगे हुए थे। इस तत्त्व को अलग कर उन्होंने अक्टूबर 1921 में प्रदर्शित किया कि यह तत्त्व शरीर में ग्लूकोज का निस्तारण करने में अहम भूमिका निभाता है और इसकी कमी होने से मधुमेह रोग हो जाता है। इस तत्त्व को इंसुलिन का नाम दिया गया। इसकी खोज मधुमेह के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

14 नवम्बर को फ्रेडरिक बैटिंग का जन्म दिवस है। अतरू विश्व मधुमेह दिवस हेतु इस तिथि का चयन किया गया। फ्रेडरिक बेटिंग के योगदान को याद रखने के लिए इंटरनेशनल डायबेटिक फेडरेशन द्वारा 14 नवम्बर को दुनिया के 140 देशों में मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ के सतत प्रयास के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्ततरू मधुमेह की चुनौती को स्वीकारा और दिसम्बर 2006 में इसे अपने स्वास्थ कायक्रमों की सूची में शामिल किया। सन् 2007 से अब यह संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सूची में शामिल होने का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश अपनी स्वास्थ्य सम्बंधी नीति.निर्धारण में इसे महत्त्व दे रहें हैं। 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को अंगीकार करने के बाद इस का प्रतीक चिह्न नीला छल्ला चुना गया है। छल्ला या वृत्तए निरंतरता का प्रतीक है। वृत्त इस बात का प्रतीक है विश्व के सभी लोग इस पर काबू पाने के लिये एकजुट हों। नीला रंग आकाशए सह्योग और व्यापकता का प्रतीक है। इस प्रतीक चिह्न के साथ मधुमेह के लिए एकजुटता सूत्र वाक्य दिया गया है।

भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। खानपान की खराबी और शारीरिक श्रम की कमी के कारण पिछले दशक में मधुमेह होने की दर दुनिया के हर देश में बढ़ी है। भारत में इसका सबसे विकृत स्वरूप उभरा है जो बहुत भयावह है। जीवनशैली में अनियमितता मधुमेह का बड़ा कारण है। एक दशक पहले भारत में मधुमेह होने की औसत उम्र चालीस साल की थी जो अब घट कर 25 से 30 साल हो चुकी है। 15 साल के बाद ही बड़ी संख्या में लोगों को मधुमेह का रोग होने लगा है। कम उम्र में इस बीमारी के होने का सीधा मतलब है कि चालीस की उम्र आते.आते भारत में 1995 में मधुमेह रोगियों की संख्या 1 करोड़ 90 लाख थीए जो 2008 में बढ़कर चार करोड़ हो गई है। अनुमान है कि 2030 में मधुमेह रोगियों की संख्या आठ करोड़ के आसपास हो जाएगी।

भारत सरीखे देशों में करीब 340 से 350 लाख व्यक्ति इस व्याधि का शिकार हैं, जो एक विश्व रिकार्ड है। भारत में 17 प्रतिशत शहरी एवं 2.5 प्रतिशत ग्रामीण जनता इस बीमारी से पीड़ित हैं। जिसमें एक करोड़ लोगों को डायबिटिक पैरों का खतरा होगा। यह मधुमेह रोगियों में सर्वाधिक गम्भीर, जटिल व खर्चीली बीमारी है। इस रोग के परिणाम स्वरूप शरीर के निचले हिस्से के अंगों में विच्छेदन की संख्या बढ़ी है। मधुमेह डायबिटीज के कारण ही किडनी की खराबीए हृदय आघातए पैरों का गैन्ग्रीन और आंखों का अन्धापन अब भारत की मुख्य स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है।

एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को मधुमेह की आशंका अधिक होती है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवम्बर से पहले एसआरएल डायग्नॉस्टिक्स ने 2014 से 2017 के बीच पिछले साढ़े तीन साल में 63 लाख से अधिक नमूनों का विश्लेषण कियाए जिसमें सामने आया कि 21 फीसदी पुरुषों और 17.3 फीसदी महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक था। 46.60 साल के आयुवर्ग में मधुमेह के सबसे ज्यादा मामले पाये गये और 71 फीसदी लोगों को रक्त शर्करा की शिकायत थी। शहरवार विश्लेषण की बात करें तो देश के अन्य शहरों की तुलना में मुंबई और कोलकाता में मधुमेह के सबसे ज्यादा मामले पाये गये। जिनकी संख्या क्रमशरू 23.74 फीसदी और 22.07 फीसदी रही है। विशेषज्ञो का मानना है कि अगर मधुमेह रोग इसी दर से बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में भारत मधुमेह की दृष्टि से चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की राजधानी बन जाएगा।

गर्भावस्था में शुगर पर ध्यान नहीं देने से युवा पीढ़ी डायबिटीज की चपेट में आ रही है। समय रहते नहीं चेते तो स्थिति भयावह होगी। डॉक्टरों ने बताया कि पांच में से दो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान रक्त में शुगर का स्तर बढ्ने से पीड़ित हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज को नियंत्रित नहीं किया गया तो पैदा होने वाले शिशु साइज में बड़े और वजन 3०5 किलो से अधिक होता है। उनमें मधुमेहए हृदय रोग का खतरा दस गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से मधुमेह महामारी बनती जा रही है।

बदलती जीवन शैली और ठोस, उच्च ऊर्जा युक्त भोजन की प्रचुरता के कारण बच्चों में मोटापे की प्रवृत्ति इधर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी आंकड़े बताते हैं कि 7 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बीच मोटापे की दर में 1985 से 1997 के बीच दो से चार गुनी वृद्धि हुई है। भारत में किये गये एक सर्वेक्षण में 13 से 18 वर्ष के बच्चो में 18 प्रतिशत में मोटापा पाया गया। बच्चों में बढ़ते मोटापे की प्रवृत्ति एवं शारीरिक श्रम में कमी के कारण अब मधुमेह से पीड़ित बच्चे भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रहें हैं। गलत खानपान एवं आलसी जीवन शैली के कारण दिन.प्रतिदिन कम उम्र के लोगों में यह बीमारी हो रही है। अतरू भारत में ज़ोर.शोर से विश्व मधुमेह दिवस मनाने की जरूरत है।

भारत मधुमेह के रोग से पीड़ित सबसे बड़ा देश हैं। यदि इससे प्रभावित लोगों के निवास स्थान पर गौर करे तो डायबिटीज के अधिकतर केस शहरी क्षेत्र से ही आते हैं। गाँवों में इसके रोगियों की संख्या बेहद कम रही हैं जो अब बेहताशा रूप से बढ़ रही हैं। इस रोग के प्रभावों पर गौर करे तो आने वाले समय में यह भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकती हैं। विश्व मधुमेह दिवस पर अनेक संस्थाए इस विषय पर हमेशा से चौकन्ना रहने की बात करती हैं। इनकी बातो पर गौर करने की आवश्यकता हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि कभी विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों को होने की वजह से राज.रोग कहलाने वाला मधुमेह आज जीवन शैली से जुड़ी बीमारी बन चुका है जिससे बचाव के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में योग एवं व्यायाम को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले जो बीमारिया बड़ी उम्र मेंए जीवन के अंतिम पड़ाव के आस.पास होती थीए वह आजकल बच्चों में भी दिखने लगी हैं। बच्चों में मधुमेह सुनकर आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री ने कहा पहले ऐसे रोगों को राज.रोग कहा जाता था क्योंकि ऐसी बीमारिया केवल संपन्न लोगों कोए ऐश.ओ.आराम की जिंदगी जीने वालों को ही होती थीं। लेकिन हमारी जीवन शैली बदल गयी है। इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिस्ऑर्डर के नाम से जाना जाता है।

शारीरिक श्रम में कमी और खान.पान में बदलाव को कम उम्र में इन बीमारियों की वजह बताते हुए मोदी ने सलाह दी कि परिजन जागरूकता के साथ यह सुनिश्चित करें कि बच्चे खुले मैदानों में खेलने की आदत डालें। संभव हो तो परिवार के बड़े लोग भी बच्चों के साथ खुले में जाकर कर खेलें। बच्चों को लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ्ने की आदत डालें। रात में भोजन के बाद टहलने की कोशिश करें। योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहाए योगए विशेष रूप से हमारे युवा मित्रों को एक स्वस्थ जीवनशैली बनाये रखने और इससे संबंधी बीमारियों से बचाने में मददगार होगा। मधुमेह पर योग के प्रभाव के संबंध में हो रहे अध्ययनों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा इस पर एम्स में भी अध्ययन चल रहा है। अभी तक जो परिणाम आये हैंए वह बहुत उत्साहित करने वाले हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि आयुर्वेद और योग को हम सिर्फउपचार के माध्यम के तौर पर न देखें, उन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

-रमेश सर्राफ

(ये लेखक के अपने विचार है)

दिल्ली की हवा पर एनजीटी की तलवार

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की जानलेवा भयानकता को देखते हुए एक बार फिर सम.विषम कारें सड़कों पर उतारने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक सम और विषम नंबर वाले निजी वाहन एक.एक दिन के अंतराल से पांच दिन चलाए जाएंगे, लेकिन इस घोषणा के होते ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस फैसले पर अजीबो-गरीब ढंग से रोक लगा दी। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के इस आदेश पर वह प्रतिबंध तो नहीं लगा रहा है, लेकिन इस फॉर्मेले को उसकी अनुमति के बाद ही लागू किया जाए। अब इस द्विअर्थी इबारत का क्या अर्थ निकाला जाए एनजीटी की स्थापना बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए की गई थीए बावजूद उसने यह विरोधाभासी आदेश क्यों दिया यह समझ से परे है। एनजीटी ने दिल्ली में हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव की सलाह भी दी है। लेकिन यह सुझाव खर्चीला होने के कारण अप्रासंगिक है। हालांकि दिल्ली सरकार ने फायर बिग्रेडों के जरिए पेड़ों की धुलाई शुरू कर दी है। जिससे पेड़ों की वायु प्रदूषण सोखने की क्षमता बढ़ जाए। लेकिन यह उपाय कितना कारगर साबित होगा, यह कालांतर में पता चलेगा।

पिछले साल भी दिल्ली में सम.विषम फॉर्मूला लागू किया गया था। तब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण वोट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैंए जो यह साबित करे कि सम.विषम योजना लागू करने से वायु प्रदूषण नियंत्रित हुआ हो घ् दिल्ली सरकार के साथ संकट यह भी है कि जब भी वह प्रदूषण नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में पहल करती है तो दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश में रोड़ा अटका देते हैं। ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय भी यह दलील देता है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख हैं। लिहाजा दिल्ली सरकार के लिए उनकी सहमति अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं कि जब दिल्ली में वायु घ्प्रदूषण की भयानकता के चलते जब 20 प्रतिशत रोगियों की वृद्धि एकाएक हो गई होए तब उपराज्यपाल पर भी क्यों नहीं यह जुम्मेबारी डाली जाती कि वे इस समस्या के निदान की दिशा में पहल करें। यह तब और जरूरी हो जाता है जब किसी महानगर के नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाए। सारे विद्यालय बंद करना पड़ें। ऐसा अकसर सांप्रदायिक तनाव या युद्ध की स्थिति बनने पर होता है। लेकिन देश की राजधानी धुंआ.धुंआ हुई दिल्ली को प्रदूषित वायु के कहर बरप जाने के कारण झेलना पड़ रहा है। इसके फौरी कारण हरियाणाए पंजाब व उत्तरप्रदेश के खेत में फसलों के जलाए जा रहे अवशेष बताए जा रहे हैं। डंठल जलाने कोई नई बात नहीं हैए ये हजारों साल से चली आ रही परंपराए हैं। इसलिए सारा दोष इन पर मढ़नाए मूल समस्या से ध्यान भटकाना है। असली वजह बेतरतीब होता शहरीकरण और दिल्ली में बढ़ते वाहन हैं। इन वाहनों से निकले धुंए की वजह से पहली बार पता चला है कि हम अपने पेड़.पौधों में कार्बन डाईऑक्साइड सोखने की क्षमता खो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक ताजा शोध से भी पता चला है कि वायु प्रदूषण के चलते दुनिया में 30 करोड़ बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। इस स्थिति के चलते भारत में प्रति वर्ष 25 लाख लोगों की मौतें हो रही हैं। यही स्थिती बनी रही तो दिल्ली से लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे।

जाड़ों के शुरू होने से पहले और दीवाली के आसपास पिछले कई सालों से यही हालात पैदा हो रहे हैं। जागरूकता के तमाम विज्ञापन छपने के बावजूद न तो आतिशबाजी का इस्तेमाल कम हुआ और न ही पराली जलाने पर अंकुश लगा। पलारी जलाने पर तो जुर्माना वसूलने तक की बात कही गई थी। लेकिन ठोस हकीकत तो यह है कि किसानों के पास पलारी को जलाकर नष्ट करने के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यदि केंद्र व राज्य सरकारें विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय पराली से आधुनिक ईंधनए जैविक खाद और मवेशियों का आहार बनाने वाली मशीनें धान की ज्यादा पैदावार वाले क्षेत्रों में लगवा देतींए तो कहीं ज्यादा बेहतर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में ठूंठ व कचरा नहीं जलाने की अपील की थीए लेकिन इस अव्यावहारिक नसीहत का कोई असर नहीं हुआ।

वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के नजरिये से पिछले साल राष्ट्रीय हरित पंचाट ने कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उनमें से बाहरी ट्रकों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश की थी। निजी वाहनों के लिए प्रायोगिक तौर पर एक दिन सम और दूसरे दिन विषम कारें चलाने की योजना लागू की गई। ज्यादा डीजल खाने वाली नई कारों के पंजीयन पर आंशिक रोक लगाई गई थी। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ भी सख्ती बरतने की बात कही गई थी। दस साल पुरानी कारों को सड़कों से हटाने के निर्देश दिए गए। लेकिन परिणाम शून्य रहा। यहां तक की वाहनों के बेवजाह इस्तेमाल की आदत पर भी अंकुश लगाना संभव नहीं हो सका। मसलन बीमारी को जान लेने के बाद भी हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने की यही सबसे बड़ी विडंबना है। लिहाजा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार वायुमंडल में बढ़ रहा है।

अब तक तो यह माना जता रहा था कि वाहनों और फसलों के अवशेषों को जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में पेड़.पौधों की अहम् भूमिका रहती है। पेड़ अपना भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह बात सच भी हैए मगर अब पहली बार देश और दुनिया में यह तथ्य सामने आया है कि बढ़ता प्रदूण पेड़.पौधों में कार्बन सोखने की क्षमता घटा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा हैए इस कारण भी पेड़ों की प्रकृति में बदलाव आया है। शहरों को हाईटैक एवं स्मार्ट बनाने की पहल भी कहर ढाने वाली है।

वाहनों की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में पेड़ों में कार्बन सोखने की क्षमता 36०75 फीसदी कम पाई गई है। यह तथ्य देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान के ताजा शोध से सामने आया है। संस्थान की जलवायु परिवर्तन व वन आकलन प्रभाव विभाग के वैज्ञानिक डॉ हुकूम सिंह ने ष्फोटो सिंथेसिस एनालाइजरष् से कर्बन सोखने की स्थिति का पता लगाया गया है। लैगेस्ट्रोमिया स्पेसियोसा नाम के पौधे पर यह अध्ययन किया गया। इसके लिए हरियाली से घिरे वन अनुसंधान संस्थान और वाहनों की अधिक आवाजाही वाली देहरादून की चकराता रोड का चयन किया गया है। बाद में इन नतीजों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उपरोक्त स्थिति सामने आई।

संस्थान के परिसर में पौधों में कार्बन सोखने की क्षमता 9०96 माइक्रो प्रति वर्गमीटर प्रति सेकेण्ड पाई गई। जबकि चकराता मार्ग पर पौधों में यह दर महज 6०3 रही। इसके कारणों की पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि पौधों की पत्तियां प्रदूषण से ढंक गई। इस हालत में पत्तियों के वह छिद्र अत्याधिक बंद पाए गए।ए जिनके माध्यम से पेड़.पौधे प्रकाश संश्लेषण ;फोटो सिंथेसिसद्ध की क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। छिद्रो को खोलने के लिए पौधे से भीतर से दबाव भी डालते हैं। दबाव का यह उल्लघंन का ग्राफभी वन परिसर के पौधों की तुलना में चकराता मार्ग के पौधों में तीन गुना अधिक रिकोर्ड किया गया। यह अध्यन संकेत दे रहा है कि इंसान ही नहीं प्रदूषित वायु से पेड़.पौधे भी बीमार होने लग गए हैं। इसलिए जिस तरह पर्यावरण पर चौतरफा मार पड़ रही हैए उसे सुधारने के लिए भी चहुंमुखी प्रयास करने होंगे। हर समस्या को लेकर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने या फिर जनहित याचिका न्यायालय के दिशा निर्देशों से भी कोई कारगार परिणाम निकलने वाले नहीं है।

-प्रमोद भार्गव,

(ये लेखक के अपने विचार है)